राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2111/2024

1. सुनील कुमार पुत्र मानाराम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी सुखमंडला चामू जोधपुर ग्रामीण राजस्थान

2. माना राम पुत्र हिरकन राम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी सुखमंडला चामू जोधपुर ग्रामीण राजस्थान

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. पुष्पा पत्नी हनुमाना राम, निवासी सुखामंडला चामू जोधपुर ग्रामीण राजस्थान----

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री बीरबल राम

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम राजपुरोहित, पी.पी

श्री आर.एस.भाटी के साथ

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>29/08/2024</u>

1. याचिकाकर्ता पिता और पुत्र इस न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 451, 452, 354 और 379 के तहत अपराधों के

लिए पुलिस स्टेशन चामू, जोधपुर ग्रामीण में दिनांक 08.05.2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 63/2023 को रद्द करने के लिए अनुग्रह की मांग कर रहे हैं, साथ ही सभी परिणामी कार्यवाही भी।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर, जोधपुर के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 12.09.2022 को याचिकाकर्ताओं ने उसके घर पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया और उसके ससुर पर हमला किया, जो घर के बाहर बैठे थे। जब शिकायतकर्ता ने हस्तक्षेप किया, तो उसके साथ भी मारपीट की गई और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायत को संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दिया, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर दर्ज की गई।

3. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, विद्वान लोक अभियोजक को सुना है, तथा केस फाइल और आरोपित एफआईआर का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता संख्या 1 की भाभी है। याचिकाकर्ता संख्या 2 याचिकाकर्ता संख्या 1 का पिता है। इससे पहले, शिकायतकर्ता के पति (याचिकाकर्ता संख्या 1 के सगे भाई) द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अपने पहले के प्रयास में विफल होने के बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 का भाई (और याचिकाकर्ता संख्या 2 का पुत्र) अब आईपीसी की धारा 354 को लागू करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी पत्नी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

4.1. उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि वास्तव में, दोनों पक्षों के बीच पहले से ही एक सिविल विवाद चल रहा है, क्योंकि उप-विभागीय अधिकारी, बालेसर के

समक्ष राजस्व वाद पहले से ही लंबित है। इसलिए, संबंधित एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

5. एफआईआर सुनने और समीक्षा करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता वास्तव में शिकायतकर्ता का साला है। इसके अलावा, यह साबित होता है कि पारिवारिक संपत्ति पर विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच राजस्व वाद संख्या 204/2022 लंबित है।

6. इस मामले के तथ्यों के मद्देनजर, तत्काल एफआईआर के पूरी तरह से प्रेरित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह इस विशेष तथ्य से और पुष्ट होता है कि शिकायतकर्ता के पति द्वारा पहले भी इसी तरह की एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया गया था। बाद में पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता नंबर 1 के पक्ष में दायर नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के साथ उक्त एफआईआर को बंद कर दिया गया था।

7. किसी भी मामले में, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा ऊपर बताए गए तर्कों से सहमत हूं।

8. यह एफआईआर प्रतिशोधात्मक कदम प्रतीत होता है। याचिकाकर्ता नंबर 1 की भाभी ने इस बार अन्य समान रूप से अविश्वसनीय और बेतुके आरोपों के अलावा एक अप्रिय आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा पानी का पंप/मोटर चुराया गया है। यह, पहली नजर में, पक्षों के संबंधों को देखते हुए बेतुका लगता है।

9. प्रासंगिक रूप से, ऐसा लगता है कि जब पुलिस अधिकारियों ने यह महसूस किया कि दूसरी शिकायत भी प्रेरित है, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 ने धारा 156 सीआरपीसी के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की और शायद

विद्वान मजिस्ट्रेट को गुमराह करके पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाला आदेश प्राप्त करने में कामयाब रहे।

10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथ्यात्मक विवरण की पृष्ठभूमि में एफआईआर के आरोपों को देखने के बाद, मेरा मानना है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए दिनांक 29.03.2023 को आदेश पारित करके स्पष्ट रूप से कानून में गंभीर अनियमितता की है। परिणामस्वरूप, चूंकि प्रश्नगत एफआईआर में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक दोष का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

11. इस प्रकार, याचिका स्वीकार की जाती है। पुलिस स्टेशन चामू, जोधपुर ग्रामीण में दिनांक 08.05.2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 63/2023 और परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

12. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।